Limited for appointing their consignment agents for distribution of their products along with names of the products;

(b) the names and addresses of the appointed consignment agents at different places, Statewise, area allotted, period, alongwith the terms of appointment rates of commission and when their terms are to expire individually; and

(c) the names of the places and area under their jurisdiction which are lying unrepresented and since when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) The norms laid down by M/s. Indian Petrochemicals Corporation Limited (IPCL) for selection of the consignment stockists are—good financial standing, adequate experience in selling industrial/consumer products, adequate warehousing facilities, office infrastructure and communication facilities. The products sold through consignment stockists are low density polyethylene, polypropylene, polypropylene copolymer, poly vinyl chloride, linear low density polyethylene and hydrocarbon resin.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 104.]

(c) IPCL is able to service the potential areas with their existing distribution network.

डबल बाटल कनैक्शनों की सुविधा

2380. **श्री पुनील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों पर वितरकों द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को जो, डबल बाटल कनैक्शन लेना चाहते हैं, डबल बाटल कनैक्शन जारी नहीं किए जाने हैं जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में डबल बाटल कनैक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में तेल कम्पनियों को आवश्यक आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) प्राथमिकता के आधार पर दिये गये एल पी जी कनैक्शनों के मामले में दो सिलिंडर वाले कनैक्शन अनुरोध किये जाने पर दिये जाते हैं।

Seventh Plan Power Targets

2381. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item in the "Hindustan Times" of 5th October, 1987 captioned "Power scenario is not too bright" to the effect that the Governmen is not in a position to achieve the target of 280 billion units during the Seventh plan period;

(b) whether Government have focussed their attention on the use of gas based turbines for power generation since natural gas is available in the country; and

(c) what other steps Government have taken to achieve the Seventh Plan targets in power generation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Yes, Sir.

(b) Proposals for setting up of gas turbine plants are examined keeping in view the availability of gas/fuel, the power requirements of the region and other relevant techno-economic considerations.

(c) The steps taken to achieve the Seventh Plan target in power generation include expediting commissioning of the power stations under implementation, taking up short gestation projects and renovation, uprating and modernisation of some of the existing power plants.

Control over Public Sector Undertakings

2382. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Parliamentary Committee on Public Undertakings has recommended that Government must exercise a certain degree of control over public sector interprises;

(b) if so, the reaction of Government to such recommendations;

(c) whether Government have taken/proposed to take to enforce some control over the public sector enterprises in order to ensure their smooth functioning; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir. The Committee on Public Undertakings in one of their reports has recommended that the Government in Public Interest must exercise a certain degree of control as it is ultimately accountable to Parliament.

(b) to (d). A White Paper on Public Enterprises is under preparation for presentation to Parliament. The paper will deal with this subject also.

सरकारी क्षेत्र के एककों को हुआ घाटा

2383. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले महीने के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के एककों को 130 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन एककों को भविष्य में घाटा न हो ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1987–88 के प्रथम छः माह के दौरान सरकारी उद्यम विभाग के 37 उद्यमों को लाभकारिता के अनन्तिम और गैर-लेखापरीक्षित अनुमान 1986–87 की तदनुरूपी अवधि में 96 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि की तुलना में कुल 133 करोड़ की हानि दर्शाता है । मुख्य रूप से मजदूरी में संशोधन/अन्तरिम सहायता, प्राकृतिक विपदायें जैसे बाढ़, अकाल, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई आदि के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ की वजह से हानि बढ़ गई। उत्पादन कार्य का बेहतर सूचकांक मूल्य के रूप में उत्पादन होगा, जो अप्रैल-सितम्बर, 1986 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1987 के दौरान 20% बढ़ गया है।

(ग) उत्पादन कार्य में सुधार लाने हेतु तथा हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में सहचारी प्रबन्ध दल का बनाया जाना, बोर्ड स्तर की रिक्तियों को समय पर भरना, आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन के लिए धन की व्यवस्था करना, समय-समय पर उत्पादन कार्य की समीक्षा करना, वित्तीय संसाधनों पर और अधिक नियंत्रण करने हेतु एककों को निर्देश देना, अधिष्ठापित सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना, बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबन्ध आदि शामिल हैं।

Installation of a waste heat power plant project in Assam

2384. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that BHEL was entrusted with the work of installation of